पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के अन्तर्गत 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने बच्चों को नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य–पुस्तकों, निपुण विद्यालयों एवं विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया

मुख्यमंत्री ने शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया, छात्र–छात्राओं को मिड–डे–मील योजना का भोजन परोसा

शिक्षा केवल सर्टिफिकेट या डिग्री उपलब्ध करने का माध्यम नहीं बल्कि, मनुष्य को मनुष्य बनाने, संस्कारित करने तथा समाज व राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री

15 अप्रैल तक चलने वाले 'स्कूल चलो अभियान' के साथ प्रत्येक शिक्षक को जुड़ना चाहिए, 01 से 15 जुलाई के बीच 'स्कूल चलो अभियान' का दूसरा चरण चलाएं

विगत 09 वर्षों में लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों से जोड़ा गया, इस बार लक्ष्य कि 03 से 06 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा आंगनबाड़ी (बाल वाटिका) में जाए और 06 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक बच्चा प्राइमरी स्कूल में नामांकित हो

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों ने अपने कठिन परिश्रम से 'ऑपरेशन कायाकल्प' को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया

नीति आयोग ने देश में शिक्षा की 'सक्सेस स्टोरी' में उ0प्र0 के 'ऑपरेशन कायाकल्प' को स्थान दिया

बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग सभी विद्यालयों में पेयजल सहित बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित हुई, परिणामस्वरूप 'ड्रॉप आउट रेट' 19 प्रतिशत से घटकर 03 प्रतिशत तक पहुंचा

प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 80 हजार करोड़ रु0 से अधिक खर्च किए जाते

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया, जिन ब्लॉकों में यह विद्यालय नहीं, उन ब्लॉकों के लिए इस बार के बजट में धनराशि का प्राविधान

प्री–प्राइमरी से इण्टरमीडिएट तक एक ही कैम्पस में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पहले चरण में दो–दो 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय' इस बार के बजट में दो–दो और विद्यालयों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही

03 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए प्री–प्राइमरी के रूप में हर आंगनबाड़ी केंद्र में 'बाल वाटिका' बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा

प्रदेश सरकार अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रु0 और शिक्षामित्रों का मानदेय 18,000 रु0 इसी महीने से लागू करने जा रही

प्रदेश सरकार ने शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइया तथा अनुदेशक आदि के लिए 05 लाख रु0 की 'कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा' की व्यवस्था की

मुख्यमंत्री ने श्री काल भैरव मन्दिर एवं श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन–पूजन किया

लखनऊ : 04 अप्रैल, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शिक्षा केवल सर्टिफिकेट या डिग्री उपलब्ध करने का माध्यम नहीं बल्कि, मनुष्य को मनुष्य बनाने, संस्कारित करने तथा समाज व राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का सशक्त माध्यम है। ईश्वर ने गुरुजनों (शिक्षकों) को इस पुनीत कार्य में योजक की भूमिका प्रदान की है। यदि शिक्षक इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तो बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सबको शिक्षित होना आवश्यक है। जब प्रत्येक शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक यह संकल्प लेगा, तभी यह राष्ट्रीय कार्य सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद वाराणसी में शिवपुर स्थित कम्पोजिट विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में शत–प्रतिशत नामांकन एवं ट्रांजिशन सुनिश्चित करने वाले व्यापक 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारम्भ करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य–पुस्तकों तथा निपुण विद्यालयों एवं विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। उन्होंने शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया तथा छात्र–छात्राओं को मिड–डे–मील योजना का भोजन परोसा। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने श्री काल भैरव मन्दिर एवं श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन–पूजन किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 अप्रैल तक चलने वाले 'स्कूल चलो अभियान' के साथ प्रत्येक शिक्षक को जुड़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ बैठकें करें। विद्यालय प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व गांवों और मोहल्लों में निकलें, हर घर का दरवाजा खटखटाएं और पूछें कि कोई बच्चा स्कूल से वंचित तो नहीं है। अभिभावकों को बताएं कि सरकार सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, आप अपने बच्चे का पंजीकरण कराइए। विगत 09 वर्षों में लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों से जोड़ा गया है। इस बार लक्ष्य है कि 03 से 06 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा आंगनबाड़ी (बाल वाटिका) में जाए और 06 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक बच्चा प्राइमरी स्कूल में नामांकित हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 'डबल इंजन' सरकार ने वर्ष में दो यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते–मोजे और स्वेटर जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। एडमिशन की प्रक्रिया जैसे ही प्रारम्भ होगी, 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। जुलाई में जब स्कूल खुलें, तो उससे पांच दिन पहले विद्यालयों की साफ–सफाई करें, खरपतवार हटाएं और पेयजल व टॉयलेट की व्यवस्था दुरुस्त करें। 01 से 15 जुलाई के बीच 'स्कूल चलो अभियान' का दूसरा चरण चलाएं ताकि एक भी बच्चा छूटने न पाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी शिक्षकों ने अपने कठिन परिश्रम से 'ऑपरेशन कायाकल्प' को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। इसका परिणाम हमारे सामने है। भारत सरकार के नीति आयोग ने देश में शिक्षा की 'सक्सेस स्टोरी' में उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कायाकल्प' को स्थान दिया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग ने उल्लिखित किया है कि कैसे 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से 01 लाख 36 हजार से अधिक विद्यालय आवश्यक बुनियादी संसाधनों से युक्त हुए हैं। किस प्रकार 'ऑपरेशन निपुण' के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी और उन्हें अक्षर एवं अंकों का ज्ञान हुआ। इन उपलब्धियों ने प्रदेश के बच्चों के मन में स्कूल जाने की ललक पैदा की है। यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों और हमारे शिक्षकों की मेहनत व परिश्रम के कारण सम्भव हो पाया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के पश्चात हम लोगों ने पहली जुलाई को 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारम्भ किया था। इससे पूर्व प्रदेश के अलग–अलग जनपदों में भ्रमण के दौरान मैंने बन्दी की कगार पर चल रहे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के भवनों की जर्जर स्थिति को देखा था। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय में छात्र संख्या लगातार कम हो रही है। उन्होंने इसका कारण पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि का अभाव बताया। 03 वर्ष पश्चात जब पुनः उस विद्यालय का भ्रमण किया तो पता चला कि विद्यालय में 250 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का चयन 'राष्ट्रपति पुरस्कार' के लिए हुआ था। यह प्रदेश सरकार के प्रयासों से सम्भव हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व शिक्षा एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। गरीब बच्चों के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। परीक्षाओं में नकल होती थी, जिसका विपरीत असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता था। एक काम चलाऊ व्यवस्था से न तो समाज का उन्नयन होता है और न ही राष्ट्र सशक्त होता है। यदि सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में धरातल पर उतारना है, तो सबको शिक्षित करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में 'ड्रॉप आउट रेट' 19 प्रतिशत से अधिक था। तीसरी, चौथी, पांचवीं या छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। हमारी सरकार ने प्रदेश भर से डेटा एकत्रित करवाया और अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूलों में पेयजल तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग सभी विद्यालयों में पेयजल सहित बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इसी का परिणाम है कि 'ड्रॉप आउट रेट' आज 19 प्रतिशत से घटकर 03 प्रतिशत तक पहुँचा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े सभी अधिकारी और शिक्षक 'ड्रॉप आउट रेट' को जीरो तक पहुँचाने के लिए कार्य करें। यह आपके लिए एक मिसाल

होगी और बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी 'सक्सेस स्टोरी' बनेगी। हम प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करते हैं। यह धनराशि शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए खर्च की जाती है। शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। प्रदेश सरकार इस कार्य में सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के जिन ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं थे, उन ब्लॉकों के लिए इस बार के बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में गरीब परिवारों की बालिकाएं पढ़ती हैं। पहले वहां केवल आठवीं तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। कुछ अभिभावक उसके बाद बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत हो गए हैं। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गयी है। अब प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पहले चरण में दो–दो 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय' और इस बार के बजट में दो–दो और विद्यालयों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। जहाँ बच्चे प्री–प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक एक ही कैम्पस में अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 06 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश लेता है। 03 से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्री–प्राइमरी के रूप में हर आंगनबाड़ी केन्द्र में 'बाल वाटिका' बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। इस कार्य के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व बनता है कि प्रत्येक अभिभावक के साथ संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते–मोजे और स्वेटर अवश्य खरीदें। सभी बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएं। ईश्वर ने शिक्षकों को देश के भविष्य को गढ़ने और तराशने की जिम्मेदारी दी है, यदि आप उसका ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे, तो आपका जीवन यशस्वी होगा। जब यह बच्चे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो आपका स्मरण करते हुए सदैव सम्मान देंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आज भी उन शिक्षकों का सम्मान करता हूं, जिन्होंने मुझे बचपन में अक्षर ज्ञान कराया। जब भी अपने शिक्षकों से मिलता हूं, उनके पैर अवश्य छूता हूं। सभी बच्चों को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। यह जानकर अच्छा लगा कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केन्द्र में कराया है। शिक्षक भी ऐसा कर सकते हैं। वह जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे का एडमिशन वहीं करायें। जब शिक्षक का बच्चा वहां पढ़ेगा, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को कॉन्वेंट या केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर उत्कृष्ट बनाना है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म, टीकाकरण पूर्ण होने, पहली कक्षा तथा छठी कक्षा में प्रवेश लेने तक प्रत्येक चरण में उसके अभिभावक के खाते में धनराशि भेजी जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 25 लाख से अधिक बेटियाँ इस योजना का लाभ ले रही हैं। शिक्षक पूरे मनोयोग से काम कर सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ

महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में हम अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये और शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपये इसी महीने से लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइयों तथा अनुदेशक आदि के लिए 05 लाख रुपये की 'कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा' की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक और अनुशासित बनाएं, अराजकतापूर्ण नहीं। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही देश की प्रगति का आधार है। हमें बच्चों को केवल रटाना नहीं है, बल्कि उदाहरणों, कविताओं और संगीत के माध्यम से कौशल युक्त ज्ञान देना है। छोटे–छोटे फॉर्मूले बनाकर समझाएंगे, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने का एक पवित्र कार्य है। यशस्वी बनने का अवसर सबको मिलता है, जो इसका लाभ उठाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सभी अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाएं। जब यह एक जन–आंदोलन बनेगा, तभी आपके कार्यों की सराहना होगी।

कार्यक्रम के दौरान 'स्कूल चलो अभियान' पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

कार्यक्रम को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल तथा बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संदीप सिंह ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान, विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा व श्री धर्मेन्द्र सिंह, विधायक डॉ0 अवधेश सिंह, श्री टी0 राम, श्री सुशील सिंह, डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी, वाराणसी के महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

————————

PN-CM-Varanasi Visit-School Chalo Abhiyaan-04 April, 2026